LOK SABHA

Tuesday, July 22, 1980/Asadha 31, 1902 (Saka).

The Lok Sabha met at Eleven of the clock.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

पेट्रोल और डीजल की खपत

*633. **श्री राम विलास पासवान:** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पेट्रोल और डीजल की कुल दैनिक खपत कितनी है; और

(ख) सरकारी कार्यालयों, अधिकारियों और मंत्रियों द्वारा की जाने वाली पेट्रोल की खपत की प्रतिशतता कितनी है और आम जनता द्वारा की जाने वाली पेट्रोल की खपत की प्रतिशतता कितनी है।

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI VEERENDRA PATIL): (a) The average daily consumption of petrol and high speed diesel oil in the country is about 4,300 tonnes and 28,600 tonnes respectively.

(b) No separate information about the consumption of petrol by Government Departments is available.

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के दूसरे खंड का जवाब तो मिला ही नहीं है। पहले वह जवाब दिलवाइये, नहीं तो मेरा एक सप्लीमेंटरी क्वश्चन चला जायेगा।

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: You must direct him to give an answer to the second part.

SHRI VEERENDRA PATIL: Sir, I would like to humbly submit this: The second part of the question, that is part (b) reads as follows:—

> "(b) the percentage of petrol consumbed by Government offices, Officers and Ministers and the percentage consumed by general public."

Now, Sir, I don't know how many vehicles are there; they can go to any petrol pump and they can get any amount of petrol. There is no rationing of petrol. There is no allocation of petrol to different States. There is no allocation of petrol to Ministries also. How is it possible for us to collect this information, Sir? If the hon. Member insists that I should collect the information I feel, Sir, it will take not less than 5 years to collect the information.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: The hon. Minister can order a sample survey.

SHRI CHANDRAJIT YADAV: Is the Government accountable or not? That is the important question. Your departments and ministries may get as much petrol as they like. Do you make them accountable or not? Why not make them accountable?

SHRI VEERENDRA PATIL: So far as our Ministry is concerned, the responsibility is not only to supply petrol to Government departments, but to all people of the country, irrespective of whether they belong to Government or private companies or public sector or anything. They can get any amount of petrol. If they want me to collect this, I will have to write to the State Governments—every State Government, every department in the State Ministry, every department in the Central Ministry to collect that information. It will take nearly 5 to 6 years.

MR. SPEAKER: You can ask for time to collect the information.

लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, पाटिल साहब कि आप इसको फाइनेन्स डिपार्टमैंट से जहां से बिल जाते हैं, वहां से ले सकें?

SHRI VEERENDRA PATIL: I would humbly submit that in the year 1979 such a question was put to my predecessor Mr. Bahuguna. He was the Minister in charge of Petroleum. He said, he will collect the information, and supply it. That was only with regard to Ministries and Central Government offices. It will not be an exaggeration if I say that it took one year for him to collect that information and supply it to the House.

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष महोदय, इनसे जवाब तो दिलवाइये ।

MR. SPEAKER: I shall look into the pros and cons of this question.

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि यदि मंत्री महोदय की नीयत साफ भी हो, तो चूंकि इसकी सीधी चोट अफसर पर है, क्योंकि हिन्दुस्तान के अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ अफसर के रख-रखाव पर, उसकी प्राइवेट गाड़ी पर और उसको रिसीव करने आदि पर खर्च होते हैं, इसलिए अफसर यह सूचना पांच साल क्या, पचास साल में भी नहीं देगा।

अध्यक्ष महोदय: आपने तो बिल्कुल निराशा में डाल दिया है। जो आशा थी, वह भी आपने खत्म कर दी है।

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष महोदय, आप को और इस सदन को जानकारी होगी कि यदि कोई सीनियर आफिसर एयरोड्रोम से उतरेगा, तो उसको रिसीव करने के लिए सैकड़ों गाड़ियां जायेंगी। यह बात मंत्रियों पर भी लागू होती है। **(व्यवधान)** अध्यक्ष महोदय, यह बहुत अहम सवाल है। हमारी राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था पेट्रोलियम पदार्थों पर निर्भर है। यह आश्चर्य की बात है कि माननीय सदस्य इसको हल्के ढंग से ले रहे हैं।

क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि सब सरकारी कार्यालयों में अफसर की एक गाड़ी होती है और एक गाड़ी उसके घर पर होती है और उन दोनों के पेट्रोल के लिए ऐसा सरकारी खजाने से जाता है? क्या सरकार ने इस फिजूलखर्ची को रोकने के लिए कोई कानून बनाया है या वह भविष्य में बनाने जा रही है? जिस तरह फर्टीलाइजर आदि सब चीजों के बारे में सैंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के अलग अलग आंकड़े रखे जाते हैं, उसी तरह क्या इस प्रकार के आंकड़े नहीं रखे जा सकते हैं कि उनके द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों पर कितना खर्च होता है, कितना सरकारी गाड़ियों पर खर्च होता है और कितना अफसरों की गाड़ियों पर? मैं समझता हूं कि वे रखे जा सकते हैं। सरकार इस फिजूलखर्ची में कटौती करने के लिए क्या कदम उठा रही है? क्या सरकार अगले वर्ष से अपनी रिपोर्ट में सैंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंटस के कार्यालयों मंत्रयों और सरकारी अफसरों पर होने वाले पेट्रोल के खर्चे के आंकड़े भी सदन में पेश करेगी?

श्री वीरेन्द्र पाटिल: गवर्नमेंट के डिपार्टमेंटस और मिनिस्ट्रीज में और स्टेट गवर्नमेंटस में पेट्रोल कितना खर्च होता है, इसका पूरा ब्योरा देना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन काम है, क्योंकि देश में पेट्रोल का राशनिंग नहीं है और कोई भी व्यक्ति किसी पेट्रोल पंप पर अपना व्हीकल ले जा कर जितना चाहे उतना पेट्रोल ले सकता है। हम पेट्रोल डीलर को यह नहीं कह सकते कि वे हिसाब रखें कि कौनसा व्हीकल गवर्नमेंट का है और कौनसा व्हीकल प्राईवेट है।

अध्यक्ष महोदय: बिल तो गवर्नमेंट के पास जाते हैं।

श्री वीरेन्द्र पाटिल: अगर माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि प्रत्येक मिनिस्ट्री में कितना खर्च होता है, तो वह इनफर्मेशन तो हम जल्दी ला सकते हैं। लेकिन उनका सवाल यह है कि देश भर में गवर्नमेंट के जितने डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज हैं, उन सब के खर्च का पूरा ब्योरा क्या है। उसके माने ये होंगे कि मुझे हर गवर्नमेंट और हर मिनिस्ट्री को खत लिखना पड़ेगा ।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य ने पूछा है कि इस बारे में सरकार क्या कदम उठा रही है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल: जहां तक पेट्रोलियम कनजम्पशन कम करने का सम्बन्ध है, हमने 1979 में भी एक सर्कुलर लैटर लिखा था

कि पेट्रोलियम कन्जम्पशन कम होना चाहिए। इस बारे में हमने मिनिस्ट्रीज और स्टेट गवर्नमेंट्स को सर्कुलर लेटर भेजा है।

श्री राम विलास पासवान: सरकार के पास इस समय कितने पेट्रोलियम पदार्थ हैं, आसाम में जो आन्दोलन हो रहा है, उससे कितनी क्षति हुई है और सरकार इमर्जेन्सी क्वोटा में हमेशा कितने पेट्रोलियम पदार्थ रखती है?

श्री वीरेन्द्र पाटिल: मेरे पास इतने आंकड़े नहीं हैं लेकिन इतना मैं कह सकता हूं पेट्रोल के बारे में कि पेट्रोल की कोई कमी नहीं है, कोई डेफिसिट नहीं है। जितना पेट्रोल चाहिए उतना पेट्रोल देने की हालत में आज मिनिस्ट्री है।

श्री राम विलास पासवान: मैंने सीधा सा प्रश्न किया कि सरकार के पास में कितना पेट्रोलियम पदार्थ है। यह तो बिलकुल सीधा सा प्रश्न है। (व्यवधान) . . उन्होंने कहा कि सफिश्येंट है। सफिश्येंट क्या होता है?

MR. SPEAKER: Sufficient means without any restraint.

श्री राम विलास पासवान: सरकार के पास में कितना है और उस के बाद आसाम के आन्दोलन के कारण कितनी क्षति हुई है?

अध्यक्ष महोदय: यह इस सवाल से पैदा नहीं होता।

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: The consumption of petrol is related to the price of petrol. If the Minister had all the information, he would have been in a position to appreciate the actual fact about consumption of petrol. I would like to know from the Minister whether the rise in price of petrol has had any effect on consumption of petrol in this country and whether it is a fact that it has had no effect on the consumption of petrol by Government, but has only squeezed the middle class of the country.

SHRI VEERENDRA PATIL: I have the figures. The total consumption of motor spirt in the current year was 1.5 million matric tons. So far as consumption of motor spirit is concerned, there is absolutely no problem because it accounts for 5 per cent of the total petrol consumption. So far as the availability. . .

MR. SPEAKER: That was not his question.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: I will repeat my question. Has the rise in prices of petrol had any effect on the consumption of petrol? Is it a fact that it has had no effect on the consumption of petrol by Government but that it has only squeezed the middle class?

SHRI VEERENDRA PATIL: The rise in price of petrol has had a very salutary effect. Its consumption is going down.

श्री मूल चंद डागा: अभी मंत्री महोदय ने अपने जवाब में एक बात कही। मैं यह कहना चाहता हूं कि पहले बहुगुणा जी ने एक फिगर दी थी कि केन्द्रीय सरकार में इतना पेट्रोल और डीजल खर्च किया गया है। उसके बाद वह जो पेट्रोल और डीजल पर खर्च होता था उस से कमी हुई है या उस से अधिक खर्च हुआ है? यह तो बता सकते हैं या नहीं बता सकते हैं? जो डाटा आलरेडी था इन के पास, जो कलेक्ट करके इन्होंने दिया था उस के आधार पर यह बता सकते हैं कि कितना कन्जम्पशन केन्द्रीय सरकार का पहले होता था और आज कितना होता है?

श्री वीरेन्द्र पाटिल: कन्जम्पशन फिगर्स मैं दे सकता हूं। जनवरी 80 से लेकर मई 80 तक की फिगर्स मेरे पास हैं। जनवरी 80 में 1 लाख 33 हजार, 200, फरवरी में 1 लाख 24 हजार 100, मार्च में 1 लाख 28 हजार 300, अप्रैल में 1 लाख 29 हजार 900 और मई में 1 लाख 47 हजार 400 । तो पेट्रोल का कन्जम्पशन ज्यादा नहीं है, इतना मैं कह सकता हूं।

श्री एम. सत्यनारायण राव: यह जितना भी कन्जम्पशन होता है, इस में गवर्नमेंट का कन्जम्पशन, जहां तक मेरी स्टेट का ताल्लुक है, 70 से 80 परसेंट कन्जम्पशन गवर्नमेंट करती है। इस सिलसिले में शायद आप ने पेपर में भी देखा होगा कि कन्जम्पशन कम करने के लिए सैटरडे को हालिडे डिक्लेयर करने की कुछ बात थी।

Has any decision been taken at a Cabinet meeting in this respect?

SHRI VEERENDRA PATIL: No decision has been taken. The Hon. Member is under the impression that 70 per cent to 80 per cent of petrol is being consumed by Government Departments. I do not agree with him. I don't have the figures, but I don't think it is 70 to 80 per cent.

SHRI NIREN GHOSH: The Minister has said there is no restraint, no limit on petrol consumption. May I know whether, in view of the abnormal rise in prices of petroleum and diesel, any restraint has been put on their consumption by Ministers and senior Government officers? Does the Minister know that the Ministers and the officers sometimes use their cars for joy rides, for sending their children to school, for marketing, and what not? Is there any restraint whatsoever, and will he consider imposing a limit on the consumption of petrol by senior officers?

SHRI VEERENDRA PATIL: He has not put any question. He wants to know how much quantity of petrol the Ministers are consuming, how much quantity of petrol they are consuming, whether they are using it for private purposes. Is it possible for me to reply?

MR. SPEAKER: You repeat the first portion of your question.

SHRI NIREN GHOSH: Will he impose any restraint on the consumption of petrol? Whether it is a fact that the Ministers and the officers use their cars for joy rides and for sending their children to schools. Will he impose any restraint on them?

SHRI VEERENDRA PATIL: The restraint is already there because the cost of petrol has gone up. We have increased it by another 65 paise. Whatever limit is fixed for them, they will be within that limit. If they exceed the limit, then they have to pay from their pockets.

श्री गिरधारी लाल व्यास: मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं क्या यह सत्य है कि कुल जितना पेट्रोल का कन्जम्शन होता है उसका 70 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के अधिकारियों पर खर्च होता है?

श्री वीरेन्द्र पाटिल: जैसा कि मैंने अभी जवाब दिया यह 70 या 80 फीसदी की जो बात है वह आपका भी गेस वर्क है और मेरा भी गेस वर्क है। हमारे पास इसके आंकड़े नहीं हैं इन आंकड़ों का पता करना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत समय लगेगे जमा करने में।

अधिक बिजली उत्पादन क्षमता

*634. **श्री के. पी सिंह देव:** क्या **ऊर्जा और कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या प्रधान मंत्री की दश में अधिक बिजली का उत्पादन करने की अपील के अनुसरण में राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में और अधिक तापीय और पन-बिजली घरों की स्थापना के लिए स्कीमें तैयार कर ली हैं और भेज दी हैं;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से राज्यों ने प्रस्ताव भेज दिए हैं और उनके विवरण क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) to (c). While inaugurating the Conference of Power Ministers of States held at New Delhi on 20th and 21st June, 1980, the Prime Minister had indicated